ग्लोबल राजस्थान एग्रोटेक मीट से तकनीक आधारित कृषि के नये युग की शुरुआत होगी- भजनलाल

मुख्यमंत्री ने बेंगलुरु में ग्राम -2026 इन्वेस्टर्स मीट में एग्रीटेक स्टार्टअप, उद्यमियों, निवेशकों व कृषि विशेषज्ञों को संबोधित किया

जयपुर, 26 अप्रैल। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि "ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट-2026" टेक्नोलॉजी और कृषि का एक ऐसा सशक्त मंच होगा, जो समृद्ध किसान, समृद्ध राजस्थान और समृद्ध भारत के निर्माण की नींव रखेगा। उन्होंने कहा कि राजस्थान में हर क्षेत्र में विकास के नये आयाम स्थापित हो रहे हैं। प्रदेश पानी एवं बिजली के क्षेत्र में तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर है, जिससे कृषि क्षेत्र में निवेश और नवाचार की अपार संभावनाएं बन रही हैं।

■ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान में फूड प्रोसेसिंग, कोल्ड चेन, जैविक कृषि, स्पाइस पार्क और कृषि तकनीक में निवेश के अनेक अवसर उपलब्ध हैं।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रविवार को बेंगलुरू में ग्राम-2026 इन्वेस्टर्स मीट का शुभारम्भ किया। इस अवसर पर उन्होंने टेक उद्यमियों एवं निवेशकों को इस आयोजन में शामिल होने का आमंत्रण दिया।

मुख्यमंत्री रविवार को बेंगलुरू में ग्राम-2026 इन्वेस्टर्स मीट में एग्री-टेक स्टार्टअप्स, उद्यमियों, निवेशकों एवं कृषि विशेषज्ञों को संबोधित कर रहे थे। शर्मा ने कहा कि किसानों को तकनीकी रूप से संपन्न बनाने की दिशा में राज्य सरकार जयपुर में 23 से 25 मई तक ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट-2026 का आयोजन कर रही है जो कि तकनीक आधारित कृषि के एक नए युग की शुरुआत होगी। इसमें प्रदेश के किसान और पशुपालकों के साथ-साथ, देश-विदेश के कृषि विशेषज्ञ, वैज्ञानिक और तकनीकी जानकार जुटेंगे। इस दौरान एग्रीटेक, ड्रोन टेक्नोलॉजी, एआई, आधुनिक खेती और फूड प्रोसेसिंग आदि से किसान रूबरू होगा। उन्होंने टेक उद्यमियों एवं निवेशकों को इस महत्वाकांक्षी आयोजन में शामिल होने का आमंत्रण दिया।

उन्होंने कहा कि राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के दौरान कृषि क्षेत्र में व्यापक स्तर पर एमओयू हुए, जिनका निरन्तर क्रियान्वयन हो रहा है। शर्मा ने कहा कि प्रदेश में फूड प्रोसेसिंग, कोल्ड चेन, जैविक कृषि, स्पाइस पार्क और कृषि तकनीक में निवेश के अनेक अवसर उपलब्ध हैं।

कृषि एवं उद्यानिकी मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि राज्य सरकार नीतिगत समर्थन, बुनियादी ढ ांचे और नवाचार को बढ़ ावा देकर एग्रीटेक सेक्टर को मजबूत कर रही है। कृषि एवं उद्यानिकी विभाग की प्रमुख शासन सचिव मंजू राजपाल ने कहा कि राजस्थान में कृषि क्षेत्र में व्यापक सुधार किए जा रहे हैं। इसके अन्तर्गत तकनीक का समावेशन करते हुए किसानों की आय बढ़ ाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

इस दौरान राजस्थान फाउण्डेशन आयुक्त मनीषा अरोड़ा, ए-वन स्टील के चेयरमैन जूलियन जालान, जैन ग्रुप के फाउंडर डॉ चेनराज रायचंद, प्राइड ग्रुप के एमडी एमएल सरावगी, राजस्थान फाउंडेशन के बेंगलुरु चैप्टर के प्रेसिडेंट सचिन पांडिया, फिक्की की एग्रीकल्चर सबकमिटी के चेयरमैन तथा किसान क्राफ्ट के सीएमडी रवीन्द्र अग्रवाल, सती एक्सपोर्ट के एमडी संदीप अग्रवाल आदि गणमान्य लोग उपस्थित थे।

प्रसिद्ध फोटोग्राफर रघु राय का निधन

नई दिल्ली, 26 अप्रैल। भारत के जाने-माने फोटोग्राफरों में शुमार रघु राय का रविवार तड़के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। वे 83 वर्ष के थे। रघु राय ने अपनी कैमरे की नजर से भारत के विविध रंगों और जीवन के अनेक पहलुओं को दुनिया के सामने पेश किया। उनके बेटे और फोटोग्राफर नितिन राय ने बताया, पिता को दो साल पहले प्रोस्टेट कैंसर हुआ था, जिसका इलाज हो गया था। इसके बाद कैंसर पेट तक फैला, वह भी ठीक हो गया। हाल ही में कैंसर उनके मस्तिष्क तक पहुंच गया था और उम्र से जुड़ी अन्य समस्याएं भी थीं। रघु राय अपने पीछे पत्नी गुरमीत, बेटे नितिन और बेटियां लगन, अवनि और पूर्वी को छोड़ गए हैं।

■ उन्होंने अपने कैमरे से भारत के विविध रंगों को दुनिया के सामने पेश किया था।

जोधपुर के खेत में एमडी ड्रग्स बनाने की फैक्ट्री पकड़ी गई

एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने रविवार सुबह 3:30 बजे छापा मारा, 100 किलो एमडी ड्रग बरामद

जोधपुर, 26 अप्रैल (कासं)। जोधपुर जिले के बालेसर इलाके में पुलिस और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने एमडी ड्रग्स बनाने की फैक्ट्री पकड़ी है। यह फैक्ट्री बालेसर के बावरली क्षेत्र के लूणावपुरा गांव में एक खेत में थी। यहां से करीब 100 किलोग्राम एमडी ड्रग्स बरामद की है तथा 6 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

सूत्रों के अनुसार, एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के आईजी विकास कुमार के निर्देशन में कार्रवाई की गई। कार्रवाई को गोपनीय रखने के लिए एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स और पुलिस की टीम ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर शनिवार देर रात मौके पर पहुंचीं तथा रात को करीब 3:30 बजे दबिश दी।

■ छापे के दौरान आरोपियों और पुलिस के बीच फायरिंग हुई, एक आरोपी के पैर में गोली लगी तथा भागने का प्रयास कर रहे एक आरोपी का पैर टूट गया।

बताया जा रहा है कि इस दौरान आरोपियों और पुलिस के बीच फायरिंग भी हुई। आरोपियों ने पुलिस टीम पर गोली चलाई। जवाब में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स और पुलिस ने भी फायरिंग की। एक आरोपी के पैर में गोली लगी, वहीं, भागने के प्रयास में एक आरोपी का पैर टूट गया।

फायरिंग की सूचना मिलते ही बालेसर, आगोलाई और बंबोर सहित आसपास के थानों की पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। कुछ अन्य संदिग्धों की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी है। पूरे क्षेत्र को सुरक्षा घेरे में ले लिया गया। घटनास्थल के आसपास आम लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई। रविवार को एफएसएल की टीम भी घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस मामले की विस्तृत जांच कर रही है। इसमें ड्रग्स के बड़े नेटवर्क का खुलासा होने की संभावना है।

माली देश के रक्षा मंत्री की आतंकी हमले में मौत

हमलावरों ने रक्षा मंत्री के घर पर कार बम से हमला किया, उनकी पत्नी व दो पोते-पोती भी मारे गए

बामाको, 26 अप्रैल। पश्चिम अफ्रीकी देश माली में शनिवार को हुए समन्वित आतंकी हमलों ने देश की सुरक्षा व्यवस्था को झकझोर दिया। इन हमलों में माली के रक्षा मंत्री सादियो कैमारा की मौत हो गई। यह हमला राजधानी बामाको के पास स्थित काटी सैन्य ठिकाना में उनके आधिकारिक आवास पर किया गया।

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, हमलावरों ने कार बम के जरिए मंत्री के घर को निशाना बनाया। इस विस्फोट में उनकी पत्नी और दो पोते-पोतियों की भी मौत होने की सूचना है। इस हमले की जिम्मेदारी अल-कायदा से जुड़े आतंकी संगठन जेएनआईएम (जमात नुसरत अल-इस्लाम वल-मुस्लिमिन) और तुआरेग विद्रोहियों ने ली है।

■ सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार, आतंकियों ने कई स्थानों पर एक साथ हमले किये, जिसमें रक्षा मंत्री के घर के अलावा बामाको का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, सेवारे, किदाल और गाओ शामिल हैं। माली की सेना ने जवाबी कार्रवाही में सैंकड़ों हमलावरों को मार गिराने का दावा किया।

सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक, यह हमला केवल काटी तक सीमित नहीं था। आतंकियों ने एक साथ कई स्थानों को निशाना बनाया, जिनमें बामाको का अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, सेवारे, किदाल और गाओ शामिल हैं। इस तरह के समन्वित हमले से स्पष्ट है कि हमलावरों ने व्यापक स्तर पर अस्थिरता फैलाने की योजना बनाई थी।

इस घटना पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने हमलों की कड़ी निंदा करते हुए माली के नागरिकों के प्रति एकजुटता व्यक्त की। उन्होंने नागरिक बुनियादी ढ ांचे की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील भी की।

माली की सेना ने दावा किया है कि जवाबी कार्रवाई में सैकड़ों हमलावरों को मार गिराया गया है और हालात को नियंत्रण में लाया जा रहा है। हालांकि, राजधानी बामाको में एहतियात के तौर पर तीन दिनों का कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। सादियो कैमारा की मौत माली की सैन्य सरकार के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि वे शासन के प्रमुख स्तंभों में से एक माने जाते थे। इस हमले के बाद देश में राजनीतिक और सुरक्षा स्थिति और अधिक जटिल होने की आशंका जताई जा रही है।

पहले चरण के मतदान में तृणमूल का अहंकार टूट चुका है- मोदी

प्रधानमंत्री ने उत्तर 24 परगना में चुनाव सभा में मतुआ समुदाय, महिला, किसान, युवाओं के मुद्दे उठाये

कोलकाता, 26 अप्रैल। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बीच भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को उत्तर 24 परगना जिलांतर्गत, ठाकुरनगर में जनसभा को संबोधित करते हुए तृणमूल कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और भाजपा के पक्ष में मतदान की अपील की। अपने भाषण में उन्होंने मतुआ समुदाय, महिलाओं, किसानों और युवाओं से जुड़े कई मुद्दों को उठाया और राज्य में परिवर्तन की जरूरत पर जोर दिया।

राज्य की राजनीति पर हमला बोलते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस मां, माटी, मानुष के नारे के साथ सत्ता में आई थी, लेकिन अब वह अपने वादों से भटक चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में सिंडिकेट राज, भ्रष्टाचार और जंगलराज का माहौल है। उन्होंने कहा कि पहले चरण के मतदान में तृणमूल का अहंकार टूट चुका है और दूसरे चरण में भाजपा की जीत सुनिश्चित है।

■ प्रधानमंत्री मोदी ने मतुआ और नमशूद्र समुदाय से कहा कि उन्हें स्थायी पहचान और अधिकार दिये जाएंगे, जो देश के अन्य नागरिकों को प्राप्त हैं।

प्रधानमंत्री ने उद्योग और रोजगार के मुद्दे पर भी राज्य सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि हुगली नदी के आसपास कभी उद्योग फलते-फूलते थे, लेकिन अब कारखानों पर ताले लग रहे हैं। जूट मिलों के बंद होने का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि तृणमूल शासन में उद्योगों को बढ़ ावा नहीं मिल रहा, जबकि केन्द्र सरकार ने जूट के न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ ाया है और उसके उपयोग को अनिवार्य किया है।

प्रधानमंत्री ने नागरिकता संशोधन अधिनियम का उल्लेख करते हुए कहा कि यह कानून शरणार्थियों को नागरिकता और अधिकार देने के लिए लाया गया है। उन्होंने मतुआ और नमशूद्र समुदाय से कहा कि उन्हें स्थायी पहचान और अधिकार दिए जाएंगे, जो देश के अन्य नागरिकों को प्राप्त हैं। उन्होंने तृणमूल पर इस मुद्दे पर भ्रामक प्रचार करने का आरोप लगाया। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अवैध घुसपैठियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और लोगों से भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार बनने पर बंगाल का विकास तेजी से होगा और राज्य देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो सकता है।

एसआई भर्ती 2021 पर सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर

जयपुर, 26 अप्रैल (कासं)। सब इंस्पेक्टर (एस.आई.) भर्ती-2021 को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एस.एल.पी. दायर हुई है। इसमें 9 याचिकाकर्ताओं ने राजस्थान हाईकोर्ट के खंडपीठ के फैसले को चुनौती है। याचिकाकर्ताओं में पायल शर्मा, महेन्द्र कुमार शर्मा, शशि दत्त, अशोक कुमार मीणा, गणेश नारायण मीणा व अन्य शामिल है। बताया जा रहा है कि, यह मामला सोमवार को सूचीबद्ध होगा। ज्ञात रहे कि राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने 4 अप्रैल 2026 को आदेश दिया था कि एस.आई. व प्लाटून कमांडर भर्ती रद्द की जाती है। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में अपीलकर्ताओं द्वारा कहा गया है कि 28 जून 2025 को गृह विभाग ने एक रिपोर्ट दी थी, जिसमें बताया गया था कि 838 अभ्यर्थियों में से केवल 6.5 प्रतिशत के खिलाफ पेपरलीक में भागीदार होने के साक्ष्य मिले हैं, जबकि 785 अभ्यर्थियों के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं मिले है।

अपीलार्थियों का आरोप है कि राजस्थान हाईकोर्ट में जिन लोगों ने याचिकाएं दायर की थीं, उनमें कुछ तथ्य छिपाए गए थे।

देश में पेट्रोलियम पदार्थों व घरेलू गैस की 100 प्रतिशत आपूर्ति

पेट्रोलियम मंत्रालय के अनुसार, 25 अप्रैल को देश भर में 51.8 लाख घरेलू एलपीजी सिलेन्डर की आपूर्ति की गई

नई दिल्ली, 26 अप्रैल। पश्चिम एशिया में जारी हालात के बीच केन्द्र सरकार ने देश में पेट्रोलियम उत्पादों और रसोई गैस की आपूर्ति को लेकर स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है और घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सरकार ने बताया कि 25 अप्रैल को देशभर में 51.8 लाख से अधिक घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति की गई, जबकि कहीं भी गैस एजेंसियों पर कमी (ड्राई-आउट) की स्थिति नहीं है।

केन्द्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार, देश में एलपीजी, पीएनजी और सीएनजी की 100 प्रतिशत आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। मंत्रालय ने लोगों से अपील की है कि वे पेट्रोल, डीजल और गैस की अनावश्यक खरीद से बचें और अफवाहों पर ध्यान न दें। मंत्रालय ने बताया कि मार्च 2026 से अब तक लगभग 5.45 लाख पीएनजी कनेक्शन सक्रिय किए गए हैं, जबकि 2.62 लाख अतिरिक्त कनेक्शनों के लिए आधारभूत ढ ांचा तैयार किया गया है। साथ ही, 42,500 से अधिक उपभोक्ताओं ने पीएनजी अपनाते हुए एलपीजी कनेक्शन सरेंडर किए हैं।

■ पैट्रोलियम मंत्रालय ने कहा कि रिफाइनरियां उच्च क्षमता पर काम कर रही हैं तथा देश में पेट्रोल-डीज़ल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है।

सरकार ने आपूर्ति प्रबंधन को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए हैं। रिफाइनरियां उच्च क्षमता पर काम कर रही हैं और पेट्रोल-डीजल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। एलपीजी की मांग को संतुलित करने के लिए वैकल्पिक ईंधनों, जैसे केरोसिन और कोयले की उपलब्धता भी बढ़ ाई गई है।

वाणिज्यिक एलपीजी की आपूर्ति को प्राथमिकता के आधार पर अस्पतालों, शैक्षिणक संस्थानों और उद्योगों को दिया जा रहा है। साथ ही प्रवासी श्रमिकों के लिए 5 किलोग्राम सिलेंडरों की आपूर्ति बढ़ ाई गई है।

मंत्रालय ने बताया कि जमाखोरी और कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए देशभर में सख्त कार्रवाई जारी है। बीते दिन 2100 से अधिक छापेमारी की गईं, जबकि 310 गैस एजेंसियों पर जुर्माना लगाया गया और 70 एजेंसियों को निलंबित किया गया है।

'अदालत आरोपियों को सरेंडर करने का निर्देश नहीं दे सकती'

नई दिल्ली, 26 अप्रैल। देश की सर्वोच्च अदालत ने अग्रिम जमानत और अदालती क्षेत्राधिकार को लेकर महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी भी आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज करना अदालत का अधिकार है। हालांकि, याचिका खारिज करते समय अदालत के पास यह शक्ति नहीं है कि वह आरोपी को संबंधित ट्रायल कोर्ट के सामने आत्मसमर्पण करने का निर्देश दे।

■ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी आरोपी की अग्रिम जमानत खारिज करने का अधिकार अदालत के पास है, पर आत्मसपर्मण करने के निर्देश देने की शक्ति नहीं है।

जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की खंडपीठ ने एक मामले की सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की।

क्या 20 साल बाद पांचना बांध से पानी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

ग्रामीणों में सामंजस्य लाने के लिए राज्य सरकार ने एक अतिरिक्त लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है, जिसके लिए 50 करोड़ रूपए भी आवंटित कर दिए गए हैं। इस अतिरिक्त लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट से 4 अतिरिक्त ग्रामों तक पानी पहुंचाया जा सकेगा।

इस मामले में दायर जनहित याचिका ग्रामोत्थान संस्था की ओर से दायर की गई है और याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता दीपक शर्मा और उनके सहायक अधिवक्ता अरविंद कुमार सिंह पैरवी के लिए पेश हुए थे।

याचिका में स्पष्ट शब्दों में बताया गया है कि पांचना बांध 1.25 लाख लोगों को सीधे-सीधे प्रभावित करता है। इस बांध के ज़रिए 46 गांव में सिंचाई की नहरों के माध्यम से पानी पहुंचाने की योजना बनाई गई थी और करीबन 40,000 बीघा जमीन की सिंचाई की जानी थी, किन्तु पानी उपलब्ध नहीं होने के कारण सिंचाई नहीं हो पा रही थी।

उल्लेखनीय है कि इस मामले में गत 5 मार्च को भी सुनवाई हुई थी, तब भी जलदाय विभाग के सुप्रीटेंडेंट इंजीनियर मौजूद थे और उन्होंने अदालत को बताया था कि इस पांचना बांध से जुड़े हुए एक लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट का निर्माण हो चुका है, जिससे करीब 13 गांवों को सिंचाई की सुविधा मुहैय्या कराई जा सके। परंतु सुपरिटेंडेंट इंजीनियर ने अदालत को यह भी बताया कि इस लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट को शुरू करने के खिलाफ कई अन्य ग्रामों के निवासियों ने विरोध प्रदर्शन किया है, क्योंकि इस लिफ्ट प्रोजेक्ट से उनके ग्रामों को कोई फायदा नहीं होगा। सुपरिटेंडेंट इंजीनियर की तरफ से अदालत को यह भी बताया गया कि विभाग ने ग्रामीणों को शांत करने के लिए एक अन्य लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट शुरू करने का प्रस्ताव भी दिया था, परंतु यह प्रस्ताव स्वयं अशोक गहलोत सरकार ने 29 मार्च 2023 को खारिज कर दिया था, क्योंकि राज्य सरकार द्वारा ही विभाग के एक अन्य लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट को रद्द कर दिया गया था इसलिए अदालत ने पहले से ही निर्मित लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट को शुरू करने के आदेश दिए थे। यह भी आदेश दिए गये थे कि जो भी समुदाय या गुट इसका विरोध करे, प्रशासन उसपर कार्यवाही करे।

■ पांचना बांध से जुड़े लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट में पानी छोड़े जाने व नहरों के नेटवर्क का विस्तार करने से क्या भाजपा सरकार एक तीर से दो निशाने भेदना चाहती है ? क्या उन मुद्दों से राजनैतिक लाभ उठाना चाहती है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत ने सचिन पायलट के बढ़ते वर्चस्व को देखते हुए जानबूझकर जनहित के कार्यों में सेंध लगाई थी?

अदालत ने अपने आदेश में अतिरिक्त महाअधिवक्ता बी एस छाबा के बयानों को भी रिकॉर्ड पर लिया, जिनमें उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार ग्रामीणों, जो प्राथमिक रूप से गुर्जर व मीणा समाज से है, के बीच में सामंजस्य नहीं बिठा पा रही है और ग्रामीणों के बीच चल रहे विवाद की आड़ में राज्य सरकार पांचना बांध से पानी छोड़ने की कार्यवाही को अंजाम नहीं दे रही है।

अतिरिक्त महाअधिवक्ता ने माना कि वर्ष 2022 में ही अदालत ने बांध से सिंचाई के लिए पानी छोड़ने के आदेश दे दिए थे, परंतु चार साल बाद भी राज्य सरकार इस बांध से पानी छोड़े जाने के आदेश को क्रियान्वित नहीं कर पा रही है। अदालत ने अतिरिक्त महाअधिवक्ता के बयानों को रिकॉर्ड पर लेते हुए कहा था कि वह राजनैतिक लाभ और हानि को मद्देनजर रखते हुए राज्य सरकार के अधिकारियों की बहानेबाजी को स्वीकार नहीं करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी गुट या समूह के प्रदर्शन करने से इतनी बड़ी स्कीम को नहीं रोका जा सकता, जिससे लाखों लोगों को फायदा होगा। अदालत ने यह भी टिप्पणी की थी कि पांचना बांध से जुड़े लिफ्ट इरिगेशन स्कीम व नहरों का निर्माणकार्य 2005 में ही समाप्त हो गया था, जिसमें हजारों – करोड़ो रुपए खर्च किए गए थे। इसलिए राज्य सरकार के अधिकारियों का यह दायित्व है कि यह स्कीम जल्द से जल्द क्रियाशील हो। अदालत ने आदेश दिए थे कि जलदाय विभाग के सुप्रीटेंडेंट इंजीनियर इस मामले में स्थिति रिपोर्ट पेश करें और बताएं कि गहलोत सरकार ने जब वर्ष 2023 में यह फैसला ले लिया था कि बचे हुए ग्रामों के लिए अतिरिक्त लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट नहीं बनाया जाएगा, उसके बाद भी पहले से निर्मित इरिगेशन प्रोजेक्ट को क्रियाशील क्यों नहीं किया गया।

इस मामले की गत सुनवाई जो 24 अप्रैल को हुई थी, उसके दौरान सुपरिटेंडेंट इंजीनियर द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है, जिसमें यह तथ्य भी उजागर हुआ है कि राजस्थान सरकार ने गहलोत सरकार के पूर्व फैसले को उलटते हुए यह फैसला किया है कि एक दूसरी लिफ्ट इरिगेशन कनाल प्रोजेक्ट को शुरू किया जाएगा, जिसे पिपलापूरा, टिकैतपूरा, उच्चेकपुरा और टोका (खारेटा) गांव में पानी पहुंचाने की व्यवस्था कराई जाएगी। सुपरिटेंडेंट की रिपोर्ट में यह स्पष्ट था कि इस नए लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट के लिए राज्य सरकार ने 50 करोड़ रुपए का आवंटन कर दिया है। इसके अलावा सुपरिटेंडेंट की रिपोर्ट में यह भी बताया गया था कि पूरे प्रोजेक्ट को ही अपग्रेड किया जाएगा। जलदाय विभाग की ओर से दी गई यह रिपोर्ट यह स्पष्ट करती है कि जिन प्रोजेक्ट्स को गत भाजपा सरकार और गहलोत सरकार, अपने अपने राजनैतिक लाभों को मद्देनजर रखते हुए जानबूझकर क्रियान्वित नहीं कर रही थीं, उन मुद्दों पर वर्तमान भाजपा सरकार अब फायदा उठा रही है।

उल्लेखनीय है कि पांचना बांध करौली राजस्थान के उस क्षेत्र में है, जहां सचिन पायलट का वर्चस्व माना जाता है। यह भी जगजाहिर है कि उन्हीं के द्वारा युवा वोटरों को जोड़ा गया था, जिन्होंने पारंपरिक राजनैतिक जातिगत रेखाओं से बाहर निकलकर कांग्रेस के पक्ष में वोट डाले थे, जिससे पिछली कांग्रेस सरकार को सत्ता का स्वाद मिला था। ऐसे में क्या यह भी स्पष्ट नहीं है कि पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत ने इन्हीं कारणों की वजह से इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को क्रियान्वित नहीं होने दिया?

क्या यही एक कारण है कि 29 मार्च 2023 को गहलोत सरकार ने सभी ग्रामीणों एवं जातियों को जोड़े रखने के लिए किए गए प्रस्ताव की पांचना बांध से जुड़े हुए एक अतिरिक्त लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट को स्वीकृति दी जाए, को अस्वीकार किया था? क्या यह सवाल कांग्रेस पार्टी व उसके कार्यकर्ता अशोक गहलोत और उनके समर्थकों से पूछ सकते है?

पचपदरा ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

आधार पर आग लगने का संभावित कारण वैक्यूम रेजिड्यू एक्सचेंजर की इनलेट लाइन पर प्रेशर गेज टैपिंग प्वाइंट से रिसाव माना जा रहा है। एचआरआरएल प्रबंधन के अनुसार, पुनर्स्थापन कार्य तेजी से जारी है और इसके अगले 3 से 4 सप्ताह में पूर्ण होने की संभावना है। क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट को मई 2026 के द्वितीय पखवाडे में पुनः प्रारंभ किए जाने की उम्मीद जताई गई है। वहीं, अन्य सहायक इकाइयां पहले से ही कमीशनिंग के उन्नत चरण में हैं। कंपनी ने बताया कि मुख्य उत्पादों एलपीजी, एमएस, एचएसडी और नैफ्था का परीक्षणात्मक उत्पादन मई 2026 में शुरू किया जाएगा, जिसके बाद इकाइयों को स्थिर कर नियमित कमीशनिंग की जाएगी। एचआरआरएल ने अपने बयान में कहा कि कंपनी परिचालन सुरक्षा, सुदृढ आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणालियों तथा उद्योग के सर्वोच्च मानकों के पालन के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

हमलावर ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

ताकि यह पता लगाया जा सके कि उसका असली मकसद क्या था और क्या वह अकेला था या किसी नेटवर्क से जुड़ा हुआ था। जहां तक ईरान कनेक्शन की बात है, अटॉर्नी जनरल ने साफ कहा कि अभी तक ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं मिला है, जांच जारी है।

देश के बैंकिंग ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

उम्मीद है, जो ज्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च और सरकारी कैपिटल व्यय से प्रेरित है। लंबे समय से प्रतीक्षित निजी पूंजीगत व्यय चक्र (केपैक्स सायकल) जीवन के संकेत दिखा रहा है, लेकिन अभी पूरी गति पकड़ने के लिए तैयार नहीं है।

मौद्रिक नीति पर आम सहमति भी समान रूप से महत्वपूर्ण है। अधिकांश बैंक उम्मीद कर रहे हैं कि निकट भविष्य में ब्याज दरें अपरिवर्तित रहेंगी, जो इस बात का संकेत है कि वर्तमान में वृद्धि और मुद्रास्फीति के बीच संतुलन उचित है। यह स्थिरता एक महत्वपूर्ण आधार प्रदान करती है, विशेष रूप से तब, जब वैश्विक अनिश्चितताएं-भू-राजनीतिक तनाव से लेकर बदलती तरलता स्थितियों तक, लगातार लंबे समय तक असर डाल रही हैं।

लेकिन, यदि शॉर्ट टर्म आउटलुक स्थिरता के बारे में है, तो लॉंग टर्म कहानी परिवर्तन के बारे में है। बैंक तेजी से यह मान रहे हैं कि खेल के नियम बदल रहे हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता अब केवल एक सहायक उपकरण नहीं हैं, यह तेजी से क्रेडिट असैसमैंट, रिस्क मैनेजमैंट और कस्टमर केयर का सैंटर बन रहा है। लगभग आधे जवाब देने वाले, ए.आई. को बैंकिंग के भविष्य को आकार देने वाली सबसे बड़ी रूकावट डालने वाली ताकत के रूप में देख रहे हैं।

साथ ही, फिनटेक और बिगटेक प्लेटफॉर्म प्रतिस्पर्धी सीमाओं को फिर से परिभाषित कर रहे हैं, जिससे बैंक प्रतिस्पर्धा और सहयोग के बीच एक नाजुक संतुलन बनाए रखने के लिए मजबूर हैं। इसमें भारत के डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे का तेजी से विस्तार भी जोड़ दें, तो एक बहुत ही अलग फायनैंशियल इकोसिस्टम की रूपरेखा उभरने लगती है।

सबसे महत्वपूर्ण बदलाव शायद रणनीतिक प्राथमिकताओं में है। क्लाइमेट रिस्क मेनेजमैंट और फायनैंशियल इन्क्लूज़न अब बैंकों के एजेंडे में शीर्ष पर हैं, जो ग्रोथ और प्रोफिटबिलिटी के पारंपरिक मेट्रिक्स से आगे बढ़ने का संकेत देते हैं। विशेष रूप से रिन्यूएबल एनर्जी फायनैंसिंग, को सबसे आशाजनक क्षेत्र माना जा रहा है, जो बैंकिंग रणनीति को राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों के साथ जोड़ता है।

सर्वेक्षण से संदेश स्पष्ट है। भारत के बैंक अब केवल पूंजी के मध्यस्थ नहीं हैं; वे वृद्धि, तकनीक और जिम्मेदारी के जटिल संगम में नेविगेट करने वाले संस्थान बन रहे हैं।

चुनौती केवल क्रेडिट विस्तार बनाए रखने की नहीं है, बल्कि तेजी से बदलते हुए माहौल के हिसाब से खुद को ढालते हुए ऐसा करना है। अभी के लिए ऐसा लगता है कि इस सैक्टर में स्टेबिलिटी और इस बदलाव को मैनेज करने का इरादा, दोनों ही हैं। क्या यह इस बैलेंस को बनाए रख पाएगा या नहीं, यह भारत के फायनैंशियल विकास के अगले फेज़ को तय करेगा।

राष्ट्रदूत हिन्दु संयुक्त परिवार की ओर से सोमेश शर्मा द्वारा ज्वाईन्ट मीडिया, आजाद मार्ग, मैन रोड, आयड, उदयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. 57928/93 जयपुर कार्यालयः सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोनः 2372634, 4103333-34, फैक्स : 0141-2373513 कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोनः 2386031, 2386032,फैक्सः0744-2386033 बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोनः 2200660, फैक्स 0151-2527371 अजमेर कार्यालयः राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोनः 2627612, फैक्सः0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन 226422,226423, फैक्सः 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोनः 230200, 230400, फैक्सः 07469-230600 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्सः 01562-256908